मंत्री विपुल गोयल की चुनाव तैयारी पैसों के दम पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ मई 2019 में होंगे या अपने निश्चित समय अक्तूबर 2019 में, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने इस बाबत कोई घोषणा नहीं की, परन्तु स्थानीय विधायक एवं राज्य के उद्योग मंत्री विपुल गोयल की तैयारियां पूरे चुनावी मोड में हैं। बीते रविवार यानी 20 जनवरी को उन्होंने सेक्टर 12 के मैदान में अपने झुग्गी बस्ती वोटरों के लिये बाकायदा लंगर लगाया तथा 25000 कंबल बांटे। इसके लिये उनके कार्यकर्ता झुग्गी बस्तियों में घर-घर गये, कंबल लेने के इच्छुक लोग़ों की लिस्ट बनाई तथा कंबल के कूपन बांटे। कूपन के बदले लोग़ों ने कंबल लिये और भर पेट भोजन कर गोयल का यशोगान करते हुए निकल गये।

इससे करीब दो सप्ताह पूर्व गोयल ने अपने ऐसे ही ग़रीब मतदाताओं को 5-5 किलोग्राम चीनी मुफ़्त बांटी थी। करीब दस हजार जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां बांटी थी। मनोरंजन के लिये अपने सागर सिनेमा हॉल में बहुचर्चित फ़िल्म बाहुबली का मुफ़्त प्रदर्शन किया। फ़िल्म के बीच-बीच में दर्शकों को गोयल की तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बता कर उनका राजनीतिक प्रचार किया गया। शिरडी सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु तो बसें गोयल जी भेजते ही रहते हैं। इन सबके अलावा विपुल गोयल ने अपने

कार्यकर्ताओं के माध्यम से उक्त बस्तियों में यह घोषणा भी करवा रखी है कि पैसों के बिना किसी कन्या का विवाह अटक रहा हो अथवा किसी बीमार का इलाज न हो पा रहा हो तो जरूरतमंद लोग आकर उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

बीती दिवाली पर गोयल द्वारा बांटी गयी मिठाई व मिठाई के डिब्बों पर छपी उनकी प्रचार सामग्री का सचित्र विवरण 'मज़दूर मोर्चा' के पाठक पहले ही पढ चुके हैं। मीडियाकर्मियों की सेवा में भी गोयल का कोई मुकाबला नहीं। दिवाली पर उन्हें गोयल द्वारा अर्पित सेवाओं का भी विस्तृत विवरण सुधी पाठक पढ ही चुके हैं।

चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर रखी है। इस खर्च की जांच एवं निगरानी करने के लिये आयकर विभाग के अफ़सरों को बाकायदा चुनाव प्रयवेक्षक तैनात किया जाता है, जाहिर है इस कवायद पर चुनाव आयोग भारी भरकम खर्चा भी करता है। परन्तु चुनाव खर्च का मीटर तो चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद ही चालू होता है। विपुल गोयल जैसे धुरंधर व्यापारी ने चुनावी बिसात बरसों पहले ही बिछा कर उस पर अंधा धुंध पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है।

दूसरी ओर समाज के जिस वंचित वर्ग पर यह खर्चा किया जा रहा है वही आजकल असल वोट बैंक भी है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में उनके लिये विपुल से बढिया नेता तो और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि सरकार चलाने वाले नेताओं का असल दायित्व क्या है? उनके लिये देश एवं समाज के सामूहिक विकास एवं समृद्धि के बारे में सोच पाना ही असंभव है। वे झुग्गी बस्तियों में सूअर बाड़ोंनुमा घरों में बसे रहने देने के लिये ही विपुल जैसे नेताओं का अहसान मानते हैं। इन बस्तियों में मामूली बिजली-पानी जैसी सुविधा भी मिल जाये तो फ़िर कहने ही क्या। बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, अच्छा रोजगार तथा ग़रीबी उन्मूलन जैसे मसलों पर ये लोग सोच ही नहीं सकते। जागरूकता के अभाव में ये लोग ग़रीबी को भगवान की देन व भाग्य का लेख मानते हैं।

ये लोग समझ ही नहीं पाते कि सत्ता के बल पर ही देश के चंद लोग अमीर से और अमीर तथा ग़रीब से और ग़रीब होते जा रहे हैं। सत्ता के बल पर ही चंद लोग़ों ने देश के तमाम संसाधनों पर कब्ज़ा कर रखा है। अपनी इसी लूट को कायम रखने के लिये सत्ताधारी चाहते हैं तथा इसके लिये प्रयास भी करते है कि लोग़ों में जागरूकता की अपेक्षा अंधविश्वास ही बढता रहे।

रैनीवैल की बड़ी पाइप लाइन का पानी 13 घंटे तक बहता रहा, इंजीनियरों की फ़ौज कुछ न कर सकी

फ़रीदाबाद (म.मो.) शनिवार 19 जनवरी को रात पौने बारह बजे रैनीवैल की एक फुट चौड़ी लाइन टूट गयी और 13 घंटे तक लाखों लीटर पानी बह गया। मिली जानकारी के अनुसार मवई गांव के आसपास वायुसेना मार्ग को चौड़ा करने का जो काम बीते करीब एक वर्ष से चल रहा था, उसके दौरान जेसीबी मशीन से टकरा कर यह पाइप लाइन फ़ट गयी। पूरे वेग के साथ जो बीसियों फ़ीट ऊंचा फ़व्वारा छूटा तो जेसीबी ड्राइवर भी डर के मारे मशीन छोड़ कर भाग गया।

लापरवाही एवं हरामखोरी का आलम यह रहा कि रात में काम चलते वक्त वहां पर कोई भी ज़िम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था जो स्थिति को सम्भालता। वहां मौजूद जनसाधारण ने एक घंटे के भीतर निगम कार्यालय, निगमायुक्त व मेयर को इसकी सूचना फ़ोन पर दी। समझा जा रहा है कि रात के एक बजे यह सूचना किसी टेलिफ़ोन ड्यूटी कर्मचारी ने ले कर रख ली क्योंकि निगमायुक्त तो क्या कोई छुट-मुट अधिकारी भी रात में अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता। लिहाजा रविवार दोपहर करीब एक बजे तक बेशकीमती पेयजल बह कर बर्बाद होता रहा।

पानी की बर्बादी रोकने के लिये कोई बहुत-कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल उस मोटर को बंद करना था जो पानी को प्रेशर से भेज रही थी । लेकिन उसे तुरंत बंद करने तक की किसी ने जरूरत नहीं समझी। करीब 13 घंटे तक पानी बर्बाद होने के बाद बंद हुई मोटर और फ़िर शुरू हुआ लाइन की मुरम्मत का काम जो करीब दो दिन तक चला, क्योंकि एमसीएफ़ के इन्जीनियरों की फ़ौज में तो एक भी फ़ौजी ऐसा नहीं जो इस काम को कर सकता, जबकि सभी एसई व चीफ़ इंजीनियर बनने की होड में लगे हैं। लिहाजा ठेकेदार को ढूंढा गया, मोल-भाव व सौदेबाज़ी करके उसे काम सौंपा गया। नगर निगम की इस कवायद के पीछे शहर के एक हिस्से में 3 दिन तक पानी की भारी किल्लत बनी रही। सेक्टर 14,15,16,17 जैसे पॉश सेक्टर भी पानी के लिये तरस गये। यदि नगर निगम प्रशासन चुस्त-दुरूस्त होता तो अव्वल तो अपनी पाइप लाइन को टूटने ही न देते और यदि टूट भी गयी थी तो 10-12 घंटे के भीतर उसकी मुरम्मत करके पानी की आपूर्ति पुन: शुरू कर देते। विदित है कि इस तरह पाइप लाइन तोड़ने वाले ठेकेदार से पूरा हर्जा-खर्चा लेने का प्रवधान है। अब यह सब तो अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे हर्जा-खर्चा वसूल कर कौनसे खाते में डालते हैं।

अवैध निर्माण व तोड़-फ़ोड़ की लूट कमाई से खूब परिचित हैं अनिता यादव

फ़रीदाबाद (म.मो.) निगमायुक्त अनिता यादव कोई विदेश से यहां नहीं आई हैं, कल तक वे भी इसी नगर निगम का एक अहम हिस्सा रह चुकी हैं। सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े व निर्माण नगर निगम की मूक सहमति से कराये जाते हैं फ़िर तोड़-फ़ोड़ के नाम पर उनसे मोटी वसूली की जाती है। पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जिसे निगम ने अवैध बताकर तोड़ा हो और उसका पुनर्निर्माण न हुआ हो। ऐसे भी अनेकों उदाहरण हैं जब तोड़-फ़ोड़ दस्ते को भेज कर निगमायुक्त ने सौदा पट जाने के बाद दस्ते को वापस बुला लिया। जहां निगम आयुक्त का यह हाल हो तो अन्य कर्मचारी भला पीछे कैसे रह सकते हैं? ऐसे में हर कर्मचारी अपनी-अपनी औकात के मुताबिक जम कर वसूली करता है।

लूट के इस दौड़ में पार्षद भला क्यों पीछे रहने लगे? पार्षद बनने के लिये करोड़ों रुपये कोई इसी उम्मीद पर खर्च करता है कि वह पार्षद बनने पर दसियों गुणा अधिक कमा लेगा। ऐसे में जिन जनप्रतिनिधियों को जनसाधारण के सुख-सुविधाओं के लिये काम करते हुये निगम के अफ़सरों की सख्ती से निगरानी करनी चाहिये थी वे खुद लूट में हिस्सेदार बन बैठते है।

निगमायुक्त अनिता ने पहले ही झटके में एक एसडीओ व एक एक्सइएन को निलम्बित करने के साथ-साथ एक ज्वायंट कमिश्नर अमरदीप जैन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जैन से पूछा गया है कि उन्होंने उक्त एसडीओ ओमप्रकाश मोड़ के विरुद्ध जांच पूरी क्यों नहीं की? तोड़-फ़ोड़ का जो काम मोड़ नहीं कर सका उसे करने के लिये उक्त एक्सीयन दीपक किंगर को भेजा गया था। तोड़-फ़ोड़ फ़िर भी नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि तोड़-फ़ोड़ न करने की एवज में मोटी रकम इन्हीं अधिकारियों ने वसूल कर पूर्व निगमायुक्त शाइन को दे दी थी। जाहिर है कि पैसा ले चुकने के बाद कोई तोड़-फ़ोड़ कैसे कर दे? वैसे भी नगर निगम में सस्पेंड होने की कोई ज्यादा परवाह नहीं की जाती। सभी जानते हैं कुछ दिन बाद फ़िर बाहर हो जायेंगे।

निगमायुक्त अनिता यादव अवैध कब्ज़ों व निर्माणों की एक काफ़ी लम्बी लिस्ट थामे बैठी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनके द्वारा निगम का पुराना अनुभव काम कर रहा है। तोड़-फ़ोड़ दस्ते पर इस तरह का दबाव बनाने के पीछे यादव का उद्देश्य शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त करने का है अथवा इसके द्वारा अपनी लूट कमाई बढाने का है, इसका निर्णय शीघ्र ही उनकी कार्यशैली से हो जायेगा।

कैदी को जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का मामला : हाईकोर्ट ने दिये जांच के आदेश

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत माह मजदूर मोर्चा में समाचार प्रकाशित हुआ था कि किस प्रकार धोखाधड़ी कर ढींगड़ा नामक बंदी को जेल से निकाल कर बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया था, करोड़ों रुपये के फ्रॉड मामले में नीमका जेल में बंद ढींगड़ा ने जेल की सख्ती से बचने एवं कुछ आरामतलब समय गुजारने के लिए बीके अस्पताल में घूमने वाले वीरेन्द्र सांगवान नाम एक फार्मासिस्ट के माध्यम से तत्कालीन सिविल सर्जन बीर सिंह सहरावत से सौदा तय किया था। यद्यपि लेन-देन की कोई रसीद तो नहीं होती परन्तु चर्चा यह थी कि सौदा पांच लाख में तय हआ था। इस बात का भी पता नहीं लग पाया था कि इस रकम में से किस-किस को क्या मिला।

डा० सहरावत के कहने पर एक-दो डाक्टरों ने तो ढींगड़ा को भर्ती करने से मना भी कर दिया था परन्तु नये-नये आये डा. बेनीवाल उनके दबाव में आ गये और उसे भर्ती कर लिया। लेकिन ज्यों ही उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने ढींगड़ा को डिसचार्ज भी कर दिया परन्तु डा. सहरावत के अधिक दबाव देने पर उसे तुरन्त ही फिर से दाखिल भी कर लिया। पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गया तो वहां से मामले की जांच के आदेश आ गये है। बेशक जांच रिपोर्ट मौजूदा सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा ने तैयार करनी है लेकिन उसकी निगरानी स्थानीय सैशन जज करेंगी।

इस तरह के मामलों में जबानी आदेश अथवा दबाव देने वाले सहरावत जैसे अफसर प्राय: मुकुर जाया करते हैं। परन्तु जानकार बताते हैं कि डा. बेनीवाल ने सहरावत के आदेश को अपने मोबाईल फोन में टेप कर लिया था। इससे बेशक डा. सहरावत तो लपेटे में आ ही जायेंगे परन्तु डा. बेनीवाल के बचाव के लिए यह कोई बहुत अच्छा कवच साबित होने वाला नहीं। डा. बेनीवाल का बचाव तो केवल अपने क्रिया कलाप को न्यायोचित सिद्ध कर पाने से ही हो सकता है।

फार्मासिस्ट सांगवान को बाहर का रास्ता दिखाया

31 दिसम्बर को डा. सहरावत के रिटायर होने के दो सप्ताह बाद कार्यवाहक सिविल सर्जन माही ने बाकायदा आफिस आर्डर जारी करके वीरेन्द्र सांगवान को बीके अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल सांगवान की असल तैनाती तो सिविल अस्पताल बल्लभगढ़ में है लेकिन उन्होंने कुछ माह पूर्व जुगाड़बाजी करके अपनी तैनाती बीके अस्पताल में अतिरिक्त रूप से करा ली थी।

मजे की बात तो यह थी कि यहां उसके पास करने को कोई काम नही था। काम तो बल्लभगढ़ वाले अस्पताल में भी उसके पास कुछ नहीं था और न ही अब है, परन्तु बीके अस्पताल तथा सिविल सर्जन के माध्यम से लूट खसूट के धंधे चलाने का स्कोप यहां अत्याधिक है, बस इसी चक्कर में उसने अपनी अतिरिक्त तैनाती यहां कराई थी जो डा. माही ने 15 जनवरी को रद्द करके उसे वापस बल्लभगढ़ भेज दिया लेकिन अपनी इस तैनाती के दौरान उसने डा. सहरावत को मोहरा बना कर जो वित्तीय अनियमितायें एवं घोटाले किये है, क्या मौजूदा सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा उनका खुलासा करेंगे अथवा पेशेवर भाईचारा निभाते हुए उनकी पर्दापोशी ही करेंगे?

बारिश की चार बूंदों ने किया स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रदूषण से निजात पाने व फ़सलों के लिये वरदान बन कर आई हल्की बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे और लोग़ों को साफ़ हवा मिल सकी वहीं नगर निगम की हरामखोरी के चलते यही बारिश शहरवासियों के लिये मुसीबत बन गई। पूरा शहर कीचड़ से भर गया। हर चौंक-चौराहे पर जल भराव के चलते लम्बे-लम्बे जाम लग गये। अजरोंदा चौंक, बडकल चौंक हमेशा की तरह इस जाम के बड़े शिकार बने।

राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीनफ़ील्ड कॉलोनी से जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास पानी से इस कदर लबालब भर गया कि उसमें तीन कारें पूरी तरह से डूब गईं। उन गाड़ियों में बैठे यात्रियों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसी जल भराव के चलते एक व्यक्ति को उस वक्त अपनी जान से हाथ धोना पड़ा जब वह अंडरपास की जगह रेलवे ट्रैक के ऊपर से उस पार जा रहा था और रेल गाड़ी की चपेट में आ गया।

यह सब घटनायें न तो पहली हैं और न ही आखिरी। बीते करीब 40 वर्षों से हर साल में तीन-चार बार यही सब इस अंडरपास पर होता आ रहा है। करीब दो साल पहले ग्रीन फ़ील्ड कॉलोनी वासी अपनी इसी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर से मिले थे। खट्टर ने इन्हें आश्वस्त करते हुये ज़िला प्रशासन को इस समस्या को हल करने का आदेश दिया था।

खट्टर के उस आदेश के बावजूद ढाक के वही तीन पात हैं। जानकार बताते हैं कि खट्टर के आदेश के बाद पानी निकासी के लिये वहां बाकायदा एक पंप लगाया गया और उसको चलाने के लिये एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई। उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि खट्टर व उनके आदेशों की औकात क्या है।

अंडरपास के इस जल भराव के लिये 'हूडा' वाले एमसीएफ़ को और एमसीएफ़ वाले 'हूडा' को जिम्मेवार ठहराकर अपना-अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दोनों ही विभागों में सैंकड़ों नालायक इंजीनियरों की फ़ौज आम जनता का लहू पीने के लिये तैनात है लेकिन कोई काम करना उनके वश का नहीं। यदि थोड़ी सी भी इंजीनियरिंग किसी को आती हो तो यहां जल निकासी के लिये न तो किसी पंप सेट की जरूरत है और न ही उसे चलाने के लिये किसी कर्मचारी की। करने वाला काम केवल इतना है कि अंडरपास को एक नाली खोदकर बगल से बह रहे बुढ़िया नाले से जोड़ना है। यदि यह काम हो जाय तो समस्या का स्थाई हल बिना किसी खर्चे के हो सकता है। परंतु समस्या का हल करना तो यहां किसी का लक्ष्य है ही नहीं।